HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 13th August, 2021

No. 20-HLA of 2021/ 64 /20593.— The Haryana Enterprises Promotion (Amendment) Bill, 2021, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:

Bill No. 20-HLA of 2021

THE HARYANA ENTERPRISES PROMOTION (AMENDMENT) BILL, 2021

A BILL

further to amend the Haryana Enterprises Promotion Act, 2016.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:

1. This Act may be called the Haryana Enterprises Promotion (Amendment) Act, 2021.

2. In section 2 of the Haryana Enterprises Promotion Act, 2016,-
   (i) after clause (k), the following clauses shall be inserted, namely:-

   ‘(ka) “medium enterprise” means the enterprise as defined under clause (g) of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (Central Act 27 of 2006);

   (kb) “micro enterprise” means the enterprise as defined under clause (h) of section 2 of the Micro Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (Central Act 27 of 2006);’;

   (ii) after clause (l), the following clause shall be inserted, namely:-

   ‘(ll) “small enterprise” means the enterprise as defined under clause (m) of section 2 of the Micro Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (Central Act 27 of 2006);’.

(2035)
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

State Government enacted Haryana Enterprises Promotion Act, 2016 to provide for simplification of regulatory framework and to assist investor in speedy implementation of projects in the State by way of granting state specific regulatory clearances/services/permission/approval/registration/license in a time bound manner through a Single Roof Mechanism.

The State Government has notified new Industrial policy namely ‘Haryana Enterprises and Employment Policy, 2020’ on 29.12.2020, which is effective from 01.01.2021 to 31.12.2025. In order to ease regulatory burden on the investor and to strengthen Haryana in Ease of Doing Business, certain regulatory reforms have been proposed under chapter 5 of the Policy which are as under:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Clause No.</th>
<th>Reform</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5.5.1</td>
<td>Clearances: MSMEs shall be given all requisite business clearances within 15 days, beyond which there will be a provision for automated deemed clearance on HEPC portal.</td>
</tr>
<tr>
<td>5.5.2</td>
<td>Inspections: No inspection shall be carried out for a period of 3 years from the date of starting a business.</td>
</tr>
<tr>
<td>5.11.8</td>
<td>Recovery of MSEs dues: The provision shall be made in Haryana Micro, Small Enterprises Facilitation Council (HMSEFC) rules to recover the outstanding payments of MSEs as arrear of land revenue.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

For implementing the above reforms, the Haryana Enterprises Promotion Rules, 2016 need to be amended. However, before moving ahead with the required amendments in Rules, definition of Micro, Small and Medium Enterprises in definition clause of Haryana Enterprises Promotion Act, 2016, is needed to be added which requires amendment in the Haryana Enterprises Promotion Act, 2016. Sections 2, of the Haryana Enterprises Promotion Act, 2016 are proposed to be amended.

DUSHYANT CHAUTALA,
Deputy Chief Minister, Haryana.


R. K. NANDAL,
Secretary.
2021 का विवेचन संख्या 20 एन.एल.ए.

हरियाणा उद्ध क्रान्ति (संशोधन) विवेचन, 2021
हरियाणा उद्ध क्रान्ति अधिनियम, 2016,
को आगे संशोधित करने के लिए

विवेचन

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो द—

1. यह अधिनियम हरियाणा लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है।

2. हरियाणा उद्ध क्रान्ति अधिनियम, 2016 की धारा 2 में—
   (i) खण्ड (ट) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्—
       ‘(टक) "मध्यम उद्ध" से अभिप्रयाण है, सूचक, लघु और मध्यम उद्ध विकास अधिनियम,
       2006 (2006 का केंद्रीय अधिनियम 27) की धारा 2 के खण्ड (छ) के अधिन यथा परिभाषित उद्ध;
   (ii) ‘(टक) "सूचक उद्ध" से अभिप्रयाण है, सूचक, लघु और मध्यम उद्ध विकास अधिनियम,
       2006 (2006 का केंद्रीय अधिनियम 27) की धारा 2 के खण्ड (ज) के अधिन यथा परिभाषित उद्ध;
   (iii) खण्ड (ट) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्—
       ‘(टक) "लघु उद्ध" से अभिप्रयाण है, सूचक, लघु और मध्यम उद्ध विकास अधिनियम,
       2006 (2006 का केंद्रीय अधिनियम 27) की धारा 2 के खण्ड (छ) के अधिन यथा परिभाषित उद्ध।
राज्य सरकार ने हरियाणा उद्यम प्रोट्साइन अधिनियम, 2016 अधिनियम किया जिससे राज्य में सेवाएं/अनुमति/
अनुयोजन/पंजीकरण/लाइसेंस समय-सीमा के तहत सिंगल रूप मैकेनिज्म के माध्यम से प्रदान करने राज्य में परियोजनाओं
के शीर्ष कायाच्यात्मक में निवेशकों की सहायता के लिए नियमक ढंगों का सरलीकरण प्रदान किया जा सके।

राज्य सरकार ने 29.12.2020 को ‘हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति, 2020’ नामक नई आयोगीक नीति अधिनियम की
है, जो 01.01.2021 से 31.12.2025 तक प्रभावी है। निवेशक पर नियमक बोझ को कम करने और व्यवसाय करने में आसानी में
हरियाणा का मजबूत करने के लिए, नीति के अंतर्गम 5 के तहत कुछ नियमक सुधारों का प्रस्ताव किया गया है जो
निम्नानुसार हैं :—

<table>
<thead>
<tr>
<th>खंड संख्या</th>
<th>सुधार</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 5.5.1     | मंजूरी: एमएसएमई को 15 दिनों के भीतर रामी आवश्यक व्यवसायिक मंजूरी दी जाएगी, जिससे बाद
|           | एनईपीसी पोर्टल पर स्वायत्त दीड्ड कीमार्फेस्ट का प्राप्त करने होगा। |
| 5.5.2     | निरीक्षण: व्यवसाय शुरु करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा। |
| 5.11.8    | एमएसई बाग्य का सुविधा: हरियाणा सूक्ष्म, लघु उद्यम सूची परिषद (एमएसईएक्सल) के नियमों में
|           | प्रवर्धन किया जाएगा तात्कि एमएसई के बाग्य मुश्किल को मूल-राजस्थ के बाग्य के रुप में वसूल किया
|           | जा सके। |

उपरोक्त सुधारों को ताला करने के लिए, हरियाणा उद्यम संकर्तन नियम, 2016 में संशोधन करने की आवश्यकता है।
नियमों में आवश्यक संशोधन के साथ आगे बढ़ने से पहले, हरियाणा उद्यम संकर्तन अधिनियम, 2016 की परिभाषा खंड में सूक्ष्म,
लघु और मध्य उद्यमों की परिभाषा को जोड़ने की आवश्यकता है, जिसके लिए हरियाणा उद्यम संकर्तन अधिनियम, 2016 में
संशोधन की आवश्यकता है। अतः हरियाणा उद्यम प्रोट्साइन अधिनियम, 2016 की धारा 2 में संशोधन का प्रस्ताव है।

चप्तीगढ़:i-1


चप्तीगढ़:

उप-मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चप्तीगढ़:


आर-के नांदन,

राज्य।